(ख) क्या वित्त मंत्रालय से परामर्श करके केन्द्रीय जांच ब्यूरो के किसी अधिकारी को उनके उत्पादन की जांच करने के लिए कहा जायेगा;

(ग) क्या यह जांच उनके बही खातों पर छापा मारकर कराई जायेगी; और

(घ) यदि हां, तो कब तक?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

Encouragement of Exports by States

3361. SHRI B. K. HARIPRASAD: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether Government are encouraging exports from all States to overcome its balance of payments problems;

(b) if so, what is the annual value of exports from each State during the Sixth and Seventh Five Year Plan periods, State-wise;

(c) whether Government have received any proposal for establishment of an Export Processing Zone in Karanataka aimed at facilitating exports;

(d) if so, what are the details thereof; and

(e) whether Government would clear this proposal at the earliest?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI P. CHIDAMBARAM): Yes, Sir.

(b) State-wise export data are not compiled.

(c) to (e) A proposal for setting up export processing zones in Bangalore and Mangalore has been received. The Government does not intend to set up any new free trade zone till the facilities created at the six existing export processing zones and the proposed zone at Vishakhatnam are fully utilised, and a carefull study of the existing zones is carried out.

आर्थिक विकास के लिए सरकार की पहल

3362. **श्री राम अवधेश सिंह:** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमरीका के विकासशील देशों के आर्थिक विकास के लिए कोई पहल कर रही है;

(ख) क्या यूरोपीय आर्थिक समुदाय के समान एशिया में एक सांझा बाजार की स्थापना करने पर विचार किया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्): (क) से (ग) भारत सरकार और साथ ही साथ उसी प्रकार के दृष्टिकोण वाले अनेक गुटनिरपेक्ष तथा अन्य विकासशील देशों ने 1989 में बेलग्रेड, यूगोस्लाविया में हुए 9 वें गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन के अवसर पर दक्षिण-दक्षिण परामर्श एवं सहयोग संबंधी शीर्ष स्तरीय समूह (जिसे जी-15) कहा जाता है स्थापित करने के लिए पहल की थी। जी-15 के उद्देश्यों में अन्य बातों के साथ-साथ दक्षिण-दक्षिण सहयोग के लिए ठोस योजनाएं तैयार करना तथा उन्हें अपनाना और ऐसी योजनाओं के पक्ष में विकासशील देशों का समर्थन प्राप्त करना शामिल है। पहली दो शिखर बैठकों से जी-15 देशों के बीच सहयोग के लिए संस्थागत आधार बनाने में मदद मिली। विशेष परियोजनाओं का पता लगाया गया और उनके कार्यान्वयन के समन्वय का उत्तरदायित्व देशों को सौंपा गया। भारत इन परियोजनाओं में से दो के लिए, अर्थात जेने बैंक फार मैडिसिनल एंड एरोमैटिक प्लांट्स एवं हर्ब्स तथा सोलर एनर्जी एप्लीकेसन्स, के लिए उत्तरदायी है।

भारत त्रिपक्षीय करार, बैंकाक करार, गाट संलेख और व्यापार अधिमानों को विश्वव्यापी प्रणाली (जी०एस०टी०पी०) का हस्ताक्षरकर्त्ता है। ये चारों ही विकासशील देशों के बीच अधिमानी व्यापार प्रबन्ध है। दक्षिण एशियाई देशों के बीच अधिमानी व्यापार प्रबन्ध के लिए भी एक प्रस्ताव है जिस पर सार्क देश विचार कर रहें हैं।

भारत-श्रीलंका व्यापार समझौता

3363. **श्री महेन्द्र सिंह लाठर:** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि भारत और श्रीलंका के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए हाल ही में एक नये समझौते पर हस्ताक्षर किये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो उक्त समझौते की शर्तें क्या-क्या